



दैनिक

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित ।

दैनिक बुद्ध का संदेश

8795951917, 9415163471

@budhakasandesh

budhakasandeshnews@gmail.com

www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

नंदिनी ठाकुर की नए शो में एंट्री, ...8

सिद्धार्थनगर

शनिवार ,02 मई 2026

वर्ष: 13 अंक : 133 पृष्ठ: 8

आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

एक विश्वास....

सम्पादक : राजेश शर्मा

महंगाई का वार: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 महंगा

वैश्विक तनाव और मध्य पूर्व में गहराते भू-राजनीतिक संकट का असर अब भारतीय रसोई और व्यापार पर दिखने लगा है। सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 की भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि, आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों (14

2 किग्रा) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें आज से 993 बढ़ा दी गई हैं। आज से दिल्ली में 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत



3071.50 होगी। घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनने के बाद से कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में कम से कम तीन बार बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले मार्च में कीमतें 144 बढ़ाई गई थीं। इसके बाद 1 अप्रैल को

कीमतों में फिर से 195.50 की बढ़ोतरी की गई। हालांकि सरकार ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और यह सुनिश्चित कर रही है कि वैश्विक बाजारों में अस्थिर हालात को देखते हुए देश के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं, लेकिन कीमतों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी का असर रेस्टोरेंट, भोजनालयों और अन्य संबंधित व्यवसायों पर काफी ज्यादा पड़ा है।

देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई अचानक बढ़ोतरी ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे जनता की जेब पर बोझ बताया है। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई बेकाबू होती जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका लगेगा। राहुल गांधी ने क्या कहा?: राहुल गांधी ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि कमर्शियल गैस महंगी होने से छोटे दुकानदारों ढाबा चलाने वालों, हलवाई और बेकरी जैसे कारोबारों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि

तो इसका सीधा असर आम जनता के खाने की थाली पर होगा। राहुल गांधी ने यह भी आशंका जताई कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अखिलेश यादव ने क्या कहा?: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तीखा तंज कसते हुए कहा कि महंगाई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद

बाजार जाकर सामान नहीं खरीदते, उन्हें आम आदमी की तकलीफ समझ नहीं आती। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार को बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी पर संसद में गंभीर चर्चा करनी चाहिए और इस जनविरोधी कदम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। जनता और छोटे कारोबारियों की बड़ी चिंता: विपक्ष का मानना है कि लगातार बढ़ती कीमतें मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रही हैं। रसोई का बजट बिगड़ने से हर घर में चिंता का माहौल है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई विस्तृत सफाई नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर सवाल उठा रहा है, उससे आने वाले दिनों में यह राजनीतिक मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।



अब 15 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर कर सकेंगे मुफ्त में सफर

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को कामर्शियल ऑपरेशन की तिथि से 15 दिन तक टोल-फ्री रखने की घोषणा की है। यूपीडा ने कन्सेशनैर्य आइआरबी और अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर को टोल वसूली रोकने के निर्देश दिए हैं, जबकि राजस्व नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 15 दिनों तक लोग मुफ्त यात्रा कर इसकी गति, गुणवत्ता और सुविधाओं का अनुभव कर सकेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक फैला यह प्रोजेक्ट 12 जिलों को जोड़ता है। पीपीपी मॉडल पर बने इस एक्सप्रेसवे में मेटेनैस और सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान दिया गया है।

महाकाल की नगरी उज्जैन में खुदाई के दौरान मिला विशालकाय शिवलिंग, हो सकता है 1000 साल पुराना!

मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर



मंदिर परिसर के पास खुदाई के दौरान एक विशाल और प्राचीन शिवलिंग मिला है। यह खोज उस समय हुई जब साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले की तैयारियों के लिए मंदिर के विस्तार का काम किया जा रहा था। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे

जब मशीन से जमीन समतल की जा रही थी, तभी मिट्टी के नीचे यह शिवलिंग दिखाई दिया।

भक्तों की उमड़ी भीड़ जैसे ही जमीन से शिवलिंग निकलने की खबर फैली, पूरे इलाके में उत्साह का माहौल बन गया। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शिवलिंग की पूजा-अर्चना की। फिलहाल खुदाई का काम रोक दिया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए वहां जमा हो रहे हैं। कई लोग इसे भगवान महाकाल का शुभ संकेत मान रहे हैं।

एक हजार साल पुराना हो सकता है इतिहास पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह शिवलिंग करीब एक हजार साल पुराना शरमारकालीन (राजा भोज के समय का) लग रहा है। इंजीनियरों का मानना है कि वहां नंदी और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी मिल सकती हैं। इससे पहले मई 2020 में भी इसी तरह की खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष और मूर्तियां मिली थीं। अब पुरातत्व विभाग इस शिवलिंग की पूरी सफाई और जांच करेगा ताकि इसके सही समय और ऐतिहासिक महत्व का पता लगाया जा सके।

विवादित बयान पर राहुल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी था।



राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक पुराने बयान से जुड़ा था, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और 8 अप्रैल को

अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह विवाद राहुल गांधी के उस बयान से शुरू हुआ था जो उन्होंने 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान दिया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ है। उन्होंने पहले संभल की निचली अदालत में शिकायत की थी, लेकिन वहां से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही माना और याचिका को कमजोर बताते हुए रद्द कर दिया।

राहुल गांधी के कौन से बयान पर हुआ था विवाद? राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा या आरएसएस से नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए यह लड़ाई अब निष्पक्ष नहीं रह गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस की विचारधारा हजारों साल पुरानी है और वे इसी विचारधारा के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

दिल्ली में सुबह की सुहानी ठंड: सामान्य से कम रहा तापमान, गरज के साथ बारिश के आसार

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। शहर के विभिन्न हिस्सों में हल्की ठंड महसूस की गई, क्योंकि न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (इडके) ने अनुमान जताया है कि दिन के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1.9 डिग्री कम है। स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है, जबकि लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री कम है। आयानगर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। शहर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह नौ बजे 128 दर्ज किया गया, जो मध्य श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, 41 निगरानी केंद्र मध्यम श्रेणी में थे, जबकि तीन केंद्र संतोषजनक श्रेणी में थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0-50 एक्यूआई "अच्छा", 51-100 "संतोषजनक", 101-200 "मध्यम", 201-300 "खराब", 301-400 "अत्यंत खराब" और 401-500 "गंभीर" माना जाता है।

मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव करेंगे हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पर महाविमर्श का शुभारंभ

भोपाल। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर 'प्रणाम! उदंत मार्तण्ड' शीर्षक से तीन दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श 8, 9 और 10 मई 2026 को भारत भवन, भोपाल होगा। शुभारंभ 8 मई को प्रातः 10:30 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव करेंगे। विषय प्रवर्तन वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सूचना आयुक्त श्री उदय माहूरकर करेंगे तथा अध्यक्षता आचार्य मिथिलेशनंदिनीकरण (अयोध्या) करेंगे। सत्रों में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, अधिवक्ता एवं लेखक जे. साई दीपक, वरिष्ठ पत्रकार जे. नंदकुमार, विष्णुप्रकाश त्रिपाठी, नगमा सहर, सईद अंसारी, उदय सिन्हा, अमिताभ अग्निहोत्री, जयंती रंगनाथन, डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह, प्रो. कृपाशंकर चौबे, प्रो. सोमा बंदोपाध्याय, विकास मिश्र, प्रफुल्ल केंतकर, प्रत्यूष रंजन, डॉ. सी. जयशंकर बाबु, शैलेश पाण्डेय, हितेश शंकर, प्रतीक त्रिवेदी, राशिद किदवाई, अनिल पाण्डेय, दिलीप शर्मा, शरद गुप्ता, सलमान रावी के अलावा 'गुल्लक' के लेखक दुर्गेश सिंह भी शामिल होंगे।

आत्मनिर्भर लद्दाख की ओर बढ़ते कदम!

अमित शाह ने करगिल में 10,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी संयंत्र की रखी आधारशिला

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में श्वेत क्रांति को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को करगिल में 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एक आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई यह परियोजना लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का

पत्थर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से पहले पेश की गई हैं। इनमें मोबाइल दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं आधुनिक दूध शीतलन प्रणाली और डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र



लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी द्वारा स्थापित

किया जा रहा है। यह परियोजना मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत लागू की जा रही है, जिसमें 12.74 करोड़ रुपये का अनुदान, 10 करोड़ रुपये की सहायता राष्ट्रीय डेयरी विकास फाउंडेशन से और शेष राशि एनयूटीडीसीएफ फंड के माध्यम से (हिमाचल प्रदेश प्रशासन के जरिये) उपलब्ध कराई जा रही

है। यह संयंत्र 350 किलोवाट सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली पर चलेगा जिससे ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में स्वच्छ तथा टिकाऊ संचालन सुनिश्चित होगा। दूध संग्रह के लिए आधुनिक मोबाइल 'मिल्क कलेक्शन' एवं 'कूलिंग सिस्टम' स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों से सीधे दूध संग्रह, गुणवत्ता संरक्षण और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम लद्दाख के डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण, किसानों की आय

बढ़ाने और खरीद प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। साथ ही बिजली से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने, दूध संग्रह को सुव्यवस्थित करने और किसानों को समय पर डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के उपाय भी किए गए हैं। भारतीय सेना के साथ नियमित दूध आपूर्ति व्यवस्था से इस क्षेत्र में डेयरी गतिविधियों को स्थिर बाजार मिला है जिससे संचालन की विश्वसनीयता बढ़ी है।

सम्पादकीय

साथ ही अक्सर बड़ी दुर्घटना का कारण बनने वाले सड़क पर खड़े वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बने और सख्त जुर्माना तय हो। कायदे से राजमार्गों पर कहीं भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। साथ ही सड़क निर्माण में किसी तकनीकी खामी की गुंजाइश न रहे, इसके लिये भी पर्याप्त सतर्कता उपाय किए जाने चाहिए। इन मार्गों पर अंधेरे में भी नजर आने वाले ...

सिंघमों और पुष्पाओं के बीच भ्रमित मतदाता

पुष्पा फिल्म देखने के बाद यही लगता है कि अपराधी के सामने पुलिस अधिाकारी की कोई हैसियत ही नहीं है चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। अपराधी होने के साथ-साथ पुष्पा राजनीति का भी चेहरा हो गया है। फिल्मों ने वैसे तो समाज के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। लड़की छेड़ने, हत्या करने, जेल से भागने, बैंक लूटने आदि का शिक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में फिल्मों का अतुलनीय योगदान रहा है। वैसे योगदान और भी कई इसी तरह के महत्वपूर्ण कार्यों में रहा है, परंतु अभी बात साधारण योगदान की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसके योगदान की हो रही है। यूपी कॉंडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को बंगाल में सिंघम का दर्जा दिया जा रहा है। उनके सामने हैं जहांगीर खान, जो पुष्पा के रूप में सामने आ रहे हैं। सिंघम, सिंघम 2 और सिंघम 3 नाम से तीन-तीन फिल्में तीन-चार साल के अंतराल पर आ चुकी हैं। हो सकता है आगे चलकर बेबी सिंघम, बाबा सिंघम भी देखने का पुण्य हमें प्राप्त हो। कमाई भी सभी सिंघमों ने जम कर की है। सिंघम फिल्मों को देखकर लगता है कि पुलिस अधिकारी के सामने अपराधी कुछ भी नहीं है चाहे वह जो भी है और जैसा भी है, यानि नेता ही क्यों न हो। दूसरी ओर पुष्पा की बात करें तो पुष्पा द राइज, और पुष्पा द रूल, आ चुकी है और पुष्पा द रैम्पेज, आने वाली है। इसका झुकेगा नहीं स्साला और हाथ से गर्दन काटने की अदा ने जो गदर मचा दिया था। गानों ने भी कुछ कम कहर नहीं बरपा रखा था। पुष्पा फिल्म देखने के बाद यही लगता है कि अपराधी के सामने पुलिस अधिकारी की कोई हैसियत ही नहीं है चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। अपराध ि होने के साथ-साथ पुष्पा राजनीति का भी चेहरा हो गया है। यकीन नहीं होता कि सुकुमार जैसे कोमल नाम के व्यक्ति ने पुष्पा को निदेशित किया होगा। बंगाल चुनाव की वर्तमान परिस्थिति में अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान को सिंघम बनाम पुष्पा के रूप में देखा जा रहा है। जहांगीर के शब्दों में ‘अजय पाल शर्मा यदि सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं। सिंघम के सामने अपराधी कुछ नहीं, पुष्पा के सामने पुलिस कुछ नहीं। पर जब बात बंगाल के चुनाव की हो रही है तो किसके सामने कौन कुछ नहीं है यह भविष्य ही बताएगा। जहांगीर ने खुद को पुष्पा घोषित कर परोक्ष रूप से कह दिया है कि झुकेगा नहीं स्साला। अजय पाल सिंह ने भी शब्दों को बदल कर कह दिया है कि अता माझी सटकली। दोनों का कहना है कि मतदाता को कोई डराए धमकाए नहीं। पर मतदाता ही क्या जिसे डराया धमकाया और ललचाया न जाए। मत के तो कई मतलब हैं। इसका एक मतलब वोट है तो दूसरा मतलब राय-विचार है। इनके साथ मत का मतलब मना करना भी है। बंगाल के मतदाता समझ नहीं पा रहे कि किस अर्थ में मतदान को लें।

देश के नीति-नियंताओं की सोच रही है कि विकास के लिए चौड़ी व रफ्तार वाली सड़कें जीवन रेखा का काम करें। हाल के वर्षों में इसी सोच के साथ राजग सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया। देश के उत्थान के लिए विकास के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी। लेकिन विकास की इस उन्नति के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी विसंगति भी सामने आई कि इन पर होने वाली दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हादसों का यह सिलसिला लगातार जारी है। सवाल उठता है कि उच्च तकनीक से तैयार आकर्षक व सुविधाजनक एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों की सुरक्षा की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। यूं तो देश की कुल सड़कों में दो फीसदी ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में इनकी संख्या तीस फीसदी हो गई है। जो हमारी गंभीर चिंता का सबब बन रहा है। ऐसे में आम नागरिकों की इस गहरी चिंता को महसूस करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने इस संकट पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार तथा इससे संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रही है अधिकारियों की उदासीनता व निर्माण से जुड़ी खामियों की वजह से राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे दुर्घटना के कारक नहीं बनने चाहिए। इस दिशा में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मार्ग खतरे का गलियारा न बने। विडंबना यह भी है कि देश में आम लोगों में ट्रैफिक से जुड़ी अनुशासन की सोच पूरी तरह से विकसित नहीं हो पायी है। खुली सड़क मिलते ही रफ्तार तेज होने लगती है, यह जानते हुए कि ये गति हमारी दुर्गति का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा तेज स्पीड में भी फोन पर बात करते रहना और शराब पीकर वाहन चलाना भी सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। यह विडंबना ही है कि भारत में दुनिया के अन्य विकसित व समकक्ष विकासशील देशों के अनुपात में वाहनों की संख्या

मौत की राह बनती सड़कों पर हो अनुशासन

तो कम है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हम अव्वल हैं। यह आंकड़ा डराता है कि साल भर में होने वाली करीब साढ़े चार लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा लाखों लोग घायल होते हैं। दुर्भाग्य से लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवनपर्यंत अंपंगता का शिकार हो जाते हैं। विडंबना यह भी कि सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ने वाले लोगों में बड़ी संख्या युवा आबादी की है। ये युवा आबादी अपने परिवार की कमाई का मुख्य जरिया होती है, उनकी मौत पूरे परिवार को गरीबी की दलदल में धकेल देती है। यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है। वास्तव में कोशिश होनी चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होने वाले प्रयास जमीनी हकीकत भी बनें, जो वास्तव में राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे को दुर्घटनाओं से निरापद बना सकें। निस्संदेह, चौड़ी व तेज गति देने वाली सड़कें देश के विकास को प्राणवायु देती हैं, लेकिन ये सड़कें यात्रियों की प्राण रक्षा करने वाली भी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि राजमार्गों पर ढाबे एक निश्चित दूरी पर हों और उनके पास ट्रकों व भारी वाहनों को खड़ा करने का पर्याप्त स्थान हो। साथ ही अक्सर बड़ी दुर्घटना का कारण बनने वाले सड़क पर खड़े वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बने और सख्त जुर्माना तय हो। कायदे से राजमार्गों पर कहीं भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। साथ ही सड़क निर्माण में किसी तकनीकी खामी की गुंजाइश न रहे, इसके लिये भी पर्याप्त सतर्कता उपाय किए जाने चाहिए। इन मार्गों पर अंधेरे में भी नजर आने वाले पर्याप्त संकेतक होने चाहिए ताकि वाहन चालकों को किसी तरह का असमंजस राजमार्ग पर चलते हुए न हो। वक्त आ गया है कि देश में दुर्घटनाओं को टालने के लिए आधुनिक यातायात प्रणाली के अनुसंधान व प्रयोग की दिशा में काम किया जाए।

कार्पोरेट व्यवस्था में श्रमिक हितों के संरक्षण की जरूरत

देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों का मानना है कि चार श्रम संहिता लागू होने की स्थिति में काम के घंटों में वृद्धि होगी, यूनियनों का पंजीकरण करवाना कठिन होगा, हड़ताल करने पर दंडात्मक कारवाई की जा सकेगी, स्थाई रोजगार की बजाय ठेका प्रणाली का प्रचलन बढ़ेगा और भर्ती व हटाना आसान होगा। यही नहीं, 300 तक श्रमिक संख्या वाले उद्योगों को श्रम विभाग की अनुमति के बिना मजदूरों को हटाने ...

एक मई को सभी देशों के श्रमिक इकट्ठे होकर शोषण, उत्पीड़न व अन्याय वाली व्यवस्था में बदलाव कर समानता का लक्ष्य आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं जो नये श्रम कानूनों व श्रमिक हितों की मौजूदा चुनौतियों के चलते और अधिक महत्वपूर्ण है। इस साल मई दिवस यानी मजदूर दिवस अभूतपूर्व परिस्थितियों में आया है। बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष सड़कों पर प्रकट हुआ। ऑटोमोबाइल, गारमेंट जैसे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की प्रमुख मांगें न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और प्रतिदिन आठ घंटे से ज्यादा काम लेने पर दोगुना ओवरटाइम थीं। ऐसी मांगों को शायद ही कोई अनुचित कह सके। लेकिन मानेसर, गुड़गांव, भिवाड़ी और नोएडा में फूटे आक्रोश को शांत करने के लिए श्रमिकों की सुनवाई करने की बजाय उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। कई गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। पिछले दिनों ऐसी ही स्थिति पानीपत रिफाइनरी के श्रमिकों के असंतोष के रूप में सामने आयी। शासन-प्रशासन की ओर से श्रमिकों के इस स्वतरूसफूर्त असंतोष के पीछे कथित संदिग्ध ताकतों का हाथ बताकर पूरे मामले को रहस्यमय बनाने की कोशिश की। लेकिन असंतोष अभी भी कायम है। वहीं ऊर्जा संकट के कारण गुजरात जैसे प्रदेशों से मजदूर पलायन कर गए हैं। इस ताजा

घटनाक्रम के विस्तार में जाने से पहले एक नजर मई दिवस के इतिहास पर डालना जरूरी है।

मई दिवस की शुरुआत साल 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मई महीने के पहले सप्ताह में हजारों औद्योगिक मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल से हुई थी। सड़कों पर आकर 8 घंटे का कार्य दिवस और कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार की मांग को लेकर रोष प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कुछ मजदूर शहीद हुए। बाद में हिंसा फैलाने के मनगढ़ंत आरोपों में मुकदमे चलाकर 6 श्रमिक नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। तभी से दुनिया के श्रमिक अपने उन शहीद साथियों को याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों से इस मानवीय नियम को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली जिसके तहत आठ घंटे काम, आठ घंटे नींद और आठ घंटे परिवार के साथ बिताना। 1889 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के आह्वान पर 1890 में 1 मई को पहली बार मई दिवस दुनियाभर में मनाया गया। तब से सभी देशों के श्रमिक 1 मई के दिन अपने-अपने शहरों में इकट्ठे होकर शोषण, उत्पीड़न वाली व्यवस्था में बदलाव कर गरिमामय जीवन व समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। अन्याय के खिलाफ वे अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं। वे साम्राज्यवादी ताकतों के साथ किये जा रहे व्यापार समझौतों के विरोध में अपने-अपने

देशों की मार्केट और संप्रभुता की हिफाजत में खड़े होते हैं और युद्धों का विरोध करते हुए विश्व शांति के पक्ष में संकल्प लेते हैं। बहरहाल, इस समय अमेरिका-इझ्राइल और ईरान युद्ध का खमियाजा पूरे विश्व के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमेशा की तरह पूंजीवादी सिस्टम के तहत कार्पोरेट जगत अपने मुनाफे की दर बनाए रखने हेतु संकट का बोझ किसान व मजदूर वर्ग के ऊपर डालने के रास्ते पर चल रहा है। ऐसे हाल में गैस की कीमतें बढ़ने से कंपनियों को अपने मुनाफे बनाए रखने के लिए श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाना आसान विकल्प दिखाई देता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के श्रमिकों को खाड़ी युद्ध की वजह से ऊर्जा के दाम बढ़ने और बेतहाशा महंगाई के कारण 8-10 हजार रुपये के मामूली वेतन में गुजारा करना असंभव हो गया। मकान किरायों में बढ़ोतरी, बच्चों की स्कूल फीस व स्वास्थ्य खर्च वृद्धि आदि के कारण मजदूर अपना गुजारा नहीं चला सकते हैं। आंदोलन भड़कने के उपरांत आनन-फानन में राज्य सरकारों ने न्यूनतम वेतन में जो वृद्धि की है वह नाकाफी है बल्कि उनका अनुपालन नहीं करवाया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसे ‘पीस रेट’ के तहत लगाया हुआ है। संगठित क्षेत्र के ये ऐसे मजदूर हैं जो असंगठित हैं। इनकी कोई वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व दुर्घटनाओं

से सुरक्षा नहीं जबकि जोखिमपूर्ण कार्य स्थितियों में इन्हें काम करना पड़ता है। शोषण के शिकार ऐसे तबकों का आवाज उठाना स्वाभाविक है। बता दें कि नव-उदारवाद के दौर में कार्पोरेट के मंसूबों के चलते वर्ष 2020 में सभी 29 श्रम कानूनों को हटाकर उनकी जगह पर चार श्रम संहिता (लेबर कोड) संसद में पारित किए गए। ट्रेड यूनियनों के तीखे विरोध के बावजूद 21 नवंबर 2025 में इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों का मानना है कि चार श्रम संहिता लागू होने की स्थिति में काम के घंटों में वृद्धि होगी, यूनियनों का पंजीकरण करवाना कठिन होगा, हड़ताल करने पर दंडात्मक कारवाई की जा सकेगी, स्थाई रोजगार की बजाय ठेका प्रणाली का प्रचलन बढ़ेगा और भर्ती व हटाना आसान होगा। यही नहीं, 300 तक श्रमिक संख्या वाले उद्योगों को श्रम विभाग की अनुमति के बिना मजदूरों को हटाने की छूट रहेगी। इसके चलते श्रम विभाग निरर्थक होकर रह जाएगा वहीं श्रमिकों की स्थिति बंधुआ जैसी हो सकती है। लेबर कोड के पक्ष में जैसी दलीलें दी जा रही हैं ठीक वैसी तीन कृषि कानूनों के संबंध में दी गई थी जिन्हें आंदोलन के बाद वापस करवाया गया था। इस समय मजदूरों के साथ किसान संगठन भी खड़े हो रहे हैं। जो आशाजनक संकेत कहे जा सकते हैं।

ऊर्जा-आत्मनिर्भरता की राह में बड़ा कदम

छोड़ने का फैसला किया है। वह भी परमाणु संलयन तकनीक पर भारी निवेश कर रहा है, जिसे वह भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के रूप में देखता है। जापानी नेतृत्व ने 2011 की फुकुशिमा आपदा से पैदा हुई सार्वजनिक चिंताओं के बावजूद अब परमाणु ऊर्जा को फिर से अपनी प्राथमिकता बनाया है। ईरान युद्ध ने, उनके परमाणु संयंत्रों को फिर से खोलने और नए संयंत्र बनाने की बातें हैं। दक्षिण कोरिया पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। वह भी अपनी असैनिक-परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है। भारत में परमाणु ऊर्जा के सतत विकास के लिए फास्ट ब्रीडर की अनिवार्यता को डॉ. होमी भाभा ने 1950 के दशक में ही समझ लिया था। उन्होंने माना कि भारत में यूरेनियम के सीमित भंडार नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को लंबे समय तक चला नहीं पाएंगे। उन्होंने यूरेनियम के कुशल उपयोग के

लिए ब्रीडर प्रणाली का सुझाव दिया। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम, दीर्घकालीन परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएफबीआर परियोजना की गतिविधि ायां 2003 में शुरू हुई और उसी वर्ष ‘भाविनी’ नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना हुई। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकैलिटी केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह भारत के दीर्घकालिक परमाणु विजन की परिपक्वता और उसकी स्वदेशी क्षमताओं की मजबूती को दर्शाती है। सीमित यूरेनियम

संसाधनों से लेकर थोरियम-संचालित भविष्य तक, भारत का तीन-चरणीय कार्यक्रम अब क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रहा है। कल्पक्कम नाभिकीय परिसर में हुई प्राप्ति उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियों में भरोसे को दर्शाती है।

जैसे-जैसे क्षमता का विस्तार होगा और नई प्रौद्योगिकियां आकार लेंगी, परमाणु ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण में कहीं अधिक केंद्रीय भूमिका निभाने लगेगी। इस समय रूस ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) संचालित कर रहा है। हालांकि, कई देशों ने प्रायोगिक फास्ट रिएक्टर विकसित या संचालित किए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और चीन शामिल हैं, पर इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम बंद हैं। इनकी लागत और तकनीकी सुझा आड़ेआई पर भारत ने इन दिक्कतों पर काबू पाया है, क्योंकि यह तकनीक ही हमारी मददगार है। भारत के पास सीमित यूरेनियम भंडार हैं लेकिन थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इसके लिए हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग ने तीन-चरणों वाला नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का पहला

चरण है, प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर), जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रयुक्त ईंान प्लूटोनियम उत्पन्न करता है, जो अगले चरण के लिए मुख्य इन्पुट बनता है। दूसरा चरण है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)। चरण 1 से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप एफबीआर इस चरण में भारत के प्रवेश का संकेत देता है। इन रिएक्टरों का उपयोग थोरियम से यूरेनियम-233 बनाने के लिए किया जाएगा, जो चरण 3 की नींव रखेगा। चरण 3 है थोरियम-आधारित रिएक्टर।

सिद्धार्थनगर का सबसे बड़ा फ्रीटींग पब्लिकेशन हाउस... फ्रीबीपीएसबीईएलएलसीआईआई

बुद्ध पब्लिकेशन ऑफसेट एण्ड प्रिन्टर्स

जौ.एस.टी., थिंक बुक/कार्ड •• कार्यालय टीकट •• स्कूल कार्ड/कार्ड/जयरी •• फ्लपेट •• कलर पोस्टर •• कलर डिप्लिमा कार्ड •• डीकट लेट पेड •• बैंक फार्म

लिकट-टीरो एजेंसी, बीनद नद्यकरपुर-सिद्धार्थनगर (3.P)

☎ 8795951917, 9453824459

Website: www.budhakasandesh.com

✉ Email: budhakasandeshnews@gmail.com



प्राप्त घोषणा की है। व्यावसायिक रूप से इस पद्धति से बिजली बनाने में अभी कई दशक लगेंगे, पर भविष्य में यह ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत साबित होगा। यह बिजली भी परमाणु के नाभिकीय में छिपे ऊर्जा स्रोत पर आधारित होगी, पर अभी प्रचलित विखंडन पर आधारित नाभिकीय ऊर्जा से एकदम अलग और सुरक्षित होगी।

नाभिकीय ऊर्जा स्वच्छ है, पर उसके साथ दुर्घटनाओं के जोखिम हैं। इस वजह से जर्मनी ने 2023 में परमाणु विखंडन (फिजन) को

महत्वपूर्ण परिघटना है। इसके पूर्ण संचालन में आने के बाद, रूस के बाद भारत, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करने वाला, दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। ईरान-युद्ध के आर्थिक दुष्प्रभावों के साथ, दुनियाभर के देश ऊर्जा सुरक्षा की तलाश में हैं। ज्यादातर देश कोयले और पेट्रोलियम के रूप में फॉसिल फ्यूल के सहारे हैं, पर अब उनके खत्म होने का समय है। वैसे भी उनके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को देखते हुए विकल्पों की तलाश चल रही है। पनबिजली, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा सबसे आगे है, क्योंकि बड़े स्तर पर वही जरूरत पूरी कर सकती है। उसके साथ भविष्य के तकनीकी विकास भी जुड़े हैं, जो नए विकल्पों को खोलेंगे। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल में संलयन (फ्यूजन) ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता

सामंथा ने मां इंति बंगाराम की रिलीज डेट की घोषणा की



स्टार हीरोइन सामंथा अभिनीत फिल्म मां इंटी बंगारम की रिलीज डेट आखिरकार तय हो गई है। फिल्म टीम ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यह प्रतिष्ठित फिल्म 15 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लंबे अंतराल के बाद सामंथा तेलुगु सिनेमा में नजर आ रही हैं, इसलिए इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म में वह एक मध्यमवर्गीय इल्लाली की भूमिका निभाएंगी और दमदार एक्शन सीक्वेंस में नजर आएंगी। ओह बेबी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकीं नंदिनी रेड्डी इस फिल्म का निर्देशन कर रही हैं, जबकि सामंथा अपनी प्रोडक्शन कंपनी ट्रालला मूविंग पिक्चर्स के बैनर तले इसका निर्माण कर रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन जाने-माने निर्देशक राज निदिमोरु ने किया है और संगीत संतोष नारायणन ने दिया है। फिल्म में गुलशन देवैया, दिगंथ, गौतमी और श्रीमुखी जैसे प्रमुख कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। सामंथा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया पोस्टर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, एक्शन से भरपूर गोल्डन हंट – इस गर्मी में सिनेमाघरों में मिलते हैं, जिससे प्रशंसकों में उत्साह और बढ़ गया है। उद्योग जगत के सूत्रों का मानना है कि गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखकर बनाई गई यह फिल्म सामंथा के करियर में एक और मील का पत्थर साबित होगी।

भूत बंगला ने दुनियाभर में काटा गदर, 13वें दिन 200 करोड़ के हुई पार, तोड़े स्त्री और थामा के रिकॉर्ड्स



गर्मियों के दौरान पेट की समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं? जानिए कारण



फिल्म राजा शिवाजी करेगी बंपर ओपनिंग? एडवांस बुकिंग में दिखा मजबूत प्रदर्शन



बता दें, फिल्म हिंदी और मराठी भाषा में रिलीज हो रही है। एडवांस बुकिंग से संकेत मिलता है कि राजा शिवाजी जबरदस्त शुरुआत करने के लिए तैयार है। संकेत यह भी बताते हैं कि फिल्म दोहरे आंकड़ों के साथ खाता खोलेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या यह महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों को टक्कर दे पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, धुंधर 2 ने 22 करोड़ के साथ क्षेत्रीय स्तर पर सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ पुष्पा 2 (18 करोड़) और छावा (17 करोड़) है।

दो हफ्ते पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की रीयूनियन फिल्म भूत बंगला दूसरे हफ्ते में भी शानदार परफॉर्म कर रही है और नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. वहीं रिलीज के 13वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड न केवल एक बड़ा आंकड़ा छू लिया. बल्कि स्त्री को भी पछाड़ दिया. जानते हैं हॉरर-कॉमेडी जॉनर की भूत बंगला ने रिलीज के 13वें दिन दुनियाभर में कितना कलेक्शन किया है?

भूत बंगला 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इससे एक दिन पहले इसके पेड ग्रीव्यू शो रखे गए थे. अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को दर्शकों से बेहद प्यार मिला और इसने भारत में अपने पहले वीकेंड में 58 करोड़ की नेट कमाई की. इसके बाद दूसरे शनिवार को इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. वहीं दूसरे वीकेंड में भी फिल्म ने दमदार कमाई कर डाली. हालांकि दूसरे सोमवार को इसके कलेक्शन में गिरावट आई, लेकिन मंगलवार को इतने कमाई में तेजी दिखाई. वहीं दूसरे बुधवार को इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सैकनलिक के आंकड़ों के मुताबिक 3.50 करोड़ की नेट कमाई की, जिससे इसका कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 124.50 करोड़ (147.90 करोड़ ग्रॉस) हो गया. फिल्म के कलेक्शन में तीसरे वीकेंड में कुछ इजाफा होने की उम्मीद है, लेकिन द डेविल विगर्स प्राडा 2 और राजा शिवाजी जैसी नई रिलीज इसकी कमाई को झटका दे सकती हैं.

भूत बंगला ने विदेशों में भी अच्छा परफॉर्म किया है. पेड ग्रीव्यू शो और पहले दिन की एवरेज शुरुआत के बाद, इसने दूसरे और तीसरे दिन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में +1 मिलियन की कमाई की, 13 दिनों के बाद, फिल्म का विदेशी ग्रॉस कलेक्शन +5.6 मिलियन है. फिलहाल, विदेशों में फिल्म का प्रदर्शन लगभग ठप हो चुका है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी रोज की कमाई 80,000 डॉलर से नीचे गिर गई है. फिर भी, इसका लक्ष्य कमाई कम होने से पहले 60 लाख डॉलर का आंकड़ा पार करना है. इसी के साथ बता दें कि फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई अब तक 200 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. इस के साथ, भूत बंगला साल 2026 में ये मील का पत्थर पार करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म और कुल मिलाकर छठी भारतीय फिल्म बन गई है. यह हॉरर-कॉमेडी जल्द ही प्रभास की फिल्म द राजा साहब (208 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी.

माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल ने 6वें दिन 2.30 करोड़ कमाए हैं, जिसके बाद भारत में कुल कारोबार 23.45 करोड़ रुपये हो गया है। अविनाश तिवारी की फिल्म गिन्नी वेड्स सन्नी 2 का हाल बेहाल है। 6वें दिन 9 लाख कमाने के बाद इसका कुल कलेक्शन 1.52 करोड़ रुपये हुआ है। उधर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 रुकने का नाम नहीं ले रही। इसने 42वें दिन 1 करोड़ कमाते हुए कुल 1,133.94 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

नंदिनी ठाकुर की नए शो में एंट्री, शब्बीर अहलूवालिया के साथ ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में निभाएंगी खास किरदार

टेलीविजन की दुनिया में हर नए शो के साथ दर्शकों को नई कहानियां और नए किरदार देखने को मिलते हैं। इन दिनों छोटे पर्दे पर एक नया शो ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा चर्चा में बना हुआ है। अब इस शो से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है।



दरअसल, अभिनेत्री नंदिनी ठाकुर भी इस कहानी का हिस्सा बनने जा रही हैं। नंदिनी इससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल और उड़ने की आशा जैसे सीरियल्स में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींच चुकी हैं। इस नए शो में नंदिनी ठाकुर ईशा नाम की एक युवा लड़की का किरदार निभाएंगी, जो निडर है, रचनात्मक सोच रखती है और अपनी बात खुलकर कहने में विश्वास करती है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए नंदिनी ठाकुर ने कहा, मुझे ईशा का किरदार शुरू से ही बेहद पसंद आया। इस किरदार से मेरा एक अलग ही जुड़ाव है। ईशा सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ईशा के अंदर महत्वाकांक्षा और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है और यही बात इस किरदार को खास बनाती है। शो में ईशा एक डिजाइनिंग दपतर में काम करती हुई नजर आएंगी। वहां वह अपने साथ काम करने वाले लोगों को नई चीजें बनाने और रचनात्मक तरीके से सोचने में मदद करती है। नंदिनी ने कहा, यह किरदार आज के युवाओं की सोच और आत्मविश्वास को काफी अच्छे तरीके से दिखाता है। इस शो में शब्बीर अहलूवालिया, श्रीति झा और ऐश्वर्या राज भाकुनी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी अपराजिता (श्रीति झा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कड़वे अतीत के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू करती है। इस दौरान उसकी मुलाकात रश्मि (शब्बीर अहलूवालिया) नाम के एक बिजनेसमैन से होती है, जिसने प्यार से दूरी बना ली है। धीरे-धीरे दोनों की जिंदगी एक-दूसरे से जुड़ने लगती है। ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा सोमवार से रविवार, रात 8:00 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होता है।

गर्मियों में पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिसके कारण पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस मौसम में लू और पानी की कमी के कारण भी पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, गर्मियों में कई लोग तले हुए और अधिक तेल वाले खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं, जो पाचन के लिए ठीक नहीं होते। आइए जाने कि गर्मियों में पेट की समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं।

खाने-पान में लापरवाही

गर्मियों में खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में सही तरीके और सही समय पर खाना बेहद जरूरी है। दरअसल, गर्मियों में लोग अपनी भूख को नजरअंदाज कर देते हैं और जब भूख लगती है तो कुछ भी खा लेते हैं, जो पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, लोग तले हुए और तेल वाले खाद्य पदार्थ खाना भी पसंद करते हैं, जो पेट के लिए ठीक नहीं होते।

पानी की कमी

गर्मियों में शरीर में पानी की कमी और लू जैसी समस्याएं पेट की समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इनसे बचने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। इसके साथ ही तरबूज, खरबूज और खीरे जैसी पानी से भरपूर सब्जियां और फलों का सेवन करें।

खाने के तुरंत बाद पानी पीना

खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत भी पेट की समस्याओं का कारण बन सकती है। अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो इस आदत को सुधार लें। खाने के एक घंटे बाद ही पानी पिएं। खाने के दौरान पानी पीने से पाचन पर बुरा असर पड़ता है और इससे गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। इससे कब्ज और अपच जैसी पेट की समस्याओं का भी खतरा बढ़ जाता है।

बाहर का खाना

गर्मियों में बाहर का खाना खाने से बचें क्योंकि इस मौसम में बाहर का खाना जल्दी खराब हो जाता है और इससे खाने की खराबी होने की संभावना बढ़ जाती है। खाने की खराबी के कारण उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप बाहर के खाने की बजाय घर का बना भोजन खाएं और घर का बना भोजन भी ताजा खाएं।

ताजे फलों का सेवन

गर्मियों में तरबूज, खरबूज और खीरे जैसे ताजे फल मिल जाते हैं। ये फल स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तरबूज में विटामिन-सी, विटामिन-ए और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है। खरबूज में विटामिन-सी, विटामिन-ए और फोलेट पाया जाता है। खीरे में भी विटामिन-सी और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है। इन फलों का सेवन करने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिल सकती है।